



2026:AHC:65743

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-- 1973 वर्ष 2026

लखन सिंह पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के लिए अधिवक्ता: विवेका नंद राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 86

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के साथ-साथ अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण की अनुमति देने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा पारित 19.01.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। केस अपराध संख्या-1845 वर्ष 2025 (लाखन सिंह बनाम अज्ञात) जो केस अपराध संख्या-110 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 302 भ०द०वि०, थाना-किरावाली, जिला आगरा के तहत विरोध आवेदन को खारिज करते हुए अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में, पुनरीक्षणकर्ता का बेटा (हरेंद्र) मृतक पंकज के साथ मोटरसाइकिल पर गया था, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली। मृतक हरेंद्र ने कथित घटना से डेढ़ साल पहले प्रतिपक्षी संख्या-2 की बेटी को फुसला लिया था, इसके बाद लड़की वापस आ गई और उसके पिता ने उसे अपने चाचा के साथ हरियाणा भेज दिया। वर्तमान घटना में मृतक हरेंद्र के व्यक्ति पर कई चोटें थीं। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी दर्ज करने के समय सूचनाकर्ता को इस तथ्य के बारे में पता नहीं था कि उसके बेटे की हत्या उसकी बेटी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और मृतक के बीच संबंध के प्रतिशोध में प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा की गई थी। मृतक के व्यक्ति पर लगी चोटों से संकेत मिलता है कि उसकी हत्या कर दी गई थी और यह मोटरसाइकिल दुर्घटना का मामला नहीं था। पुलिस ने मामले की उचित तरीके से जांच नहीं की है और अंतिम रिपोर्ट दर्ज कर दी है। पुनरीक्षण द्वारा अदालत के समक्ष विरोध आवेदन भी दायर किया गया था, लेकिन इस पर कानून के अनुसार विचार नहीं किया गया था और विरोध आवेदन को खारिज कर दिया गया था और अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी, हालांकि विचारण न्यायालय के पास विरोध आवेदन को शिकायत के रूप में मानने का विकल्प था, लेकिन इस विकल्प का भी सहारा नहीं लिया गया था, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैध मानने और पुनरीक्षण की अनुमति देने और आगे की जांच के लिए निर्देश देने या विरोध को शिकायत के रूप में मानने का अनुरोध किया।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि केवल संदेह के आधार पर सूचनाकर्ता ने तर्क दिया है कि कथित घटना से डेढ़ साल पहले मृतक द्वारा उसकी बेटी को प्रलोभन देने के कारण प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा उसके बेटे/मृतक हरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान, विवेचनाधिकारी ने उचित तरीके तरीके से सामग्री एकत्र की है और यह पाया गया कि पंकज और हरेंद्र दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे और मृतक नशे के नशे में था और घटना की तारीख को पंकज और हरेंद्र का स्थान एक ही स्थान पर था। सीसीटीवी फुटेज में भी मृतक को एक तरफ झुका हुआ देखा गया था और मोटरसाइकिल से गिरने के परिणामस्वरूप उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई थीं। पंकज को डर था कि उसे मामले में फंसाया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने मृतक हरेंद्र की हत्या की है। विचारण न्यायालय ने भी उचित तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। सूचनाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता मामले के सभी तथ्यों से अवगत है और यदि उसके पास कोई सबूत है, तो वह शिकायत दर्ज करते समय विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है। केवल संदेह के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने



मृतक हरेंद्र की हत्या की है। सूचनाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के पास शिकायत दर्ज करने का विकल्प हो सकता है और यह आदेश बाधा नहीं बनेगा।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ-साथ अभिलेखों के अवलोकन पर, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर, संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सूचनाकर्ता ने केवल प्रतिपक्षी संख्या-2 के खिलाफ मृतक की हत्या के लिए संदेह व्यक्त किया है, जिसकी बेटी को कथित घटना से डेढ़ साल पहले मृतक ने बहकाया था। इस तरह, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 19.01.2026 को पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता के पास शिकायत दर्ज करने का विकल्प हो सकता है क्योंकि जांच की आवश्यकता जैसा कुछ भी नहीं है।

तदनुसार, प्रस्तुत पुनरीक्षण का अंतिम रूप से निपटान किया जाता है।

मार्च 30, 2026

अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)